



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 1991 (श्रावण, 19 1913)  
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1991 (SRAVANA 19, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	823	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शामिल क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांख्यिक नियमों और सांख्यिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उल्लेखियां भी शामिल हैं) के द्वितीय अधिरा पाठ (जैसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकाधिकारी की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	973	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांख्यिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांख्यिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निपटक और महालेख, परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	723
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकाधिकारी की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1071	भाग III—खण्ड 2—नेटेल कार्यालय द्वारा जारी की गई नेटेलों और विज्ञापनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	843
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विधियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन समया द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांख्यिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2883
भाग II—खण्ड 2—विधियम तथा विधेयकों पर प्रकर समितियों के बिल तथा रिपोर्टें	*	भाग IV—नैर-सरकारी व्यक्तियों और नैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	108
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शामिल क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांख्यिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के सांख्यिकों को दर्ज करने वाला अनुपूरक	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शामिल क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांख्यिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

## CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	623	PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India (of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	973	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	723
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1071	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	343
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2633
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	104
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

**भाग I—खण्ड 1**  
**[PART I--SECTION 1]**

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के वंत्रानुषां और उच्चवन म्पाप्राक्ष्य द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं**

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, विसाक 22 जुलाई, 1991

शुक्रपक्ष

सं० 78-प्रेम/91—विशेष सामान्य-पत्र प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में भारत के राजपत्र के भाग—I, खण्ड—1 में 11 मई, 1974 की प्रकाशित इस सचिवालय की 28 अप्रैल, 1974 की अधिसूचना सं० 68-प्रेम/74 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है —

क्रम सं० 11 में

नेविटनेट कलन पीके-प्र राज बहुगुणा (आई० सी० 7205), 5 जुलाई—  
के स्थान पर

नेविटनेट कलन पीके-प्र राज बहुगुणा (आई० सी० 7105), 5 जुलाई—  
पढ़े

सं० 74-प्रेम/91—विशेष सामान्य-पत्र प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में भारत के राजपत्र के भाग—I, खण्ड—1 में 28 जुलाई, 1990 की प्रकाशित इस सचिवालय की 28 जनवरी, 1990 की अधिसूचना सं० 51-प्रेम/90 में निम्न-लिखित संशोधन किया जाता है —

"नियोजित में गणिका"

के स्थान पर

"नियोजित तथा जम्मू और कश्मीर की नियोजित रेखा में संक्रियाएं  
पढ़े

ए० के० उपाध्याय  
निर्देशक

रक्षा मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, विसाक 26 जुलाई 1991

संकल्प

सं० 19011/25/91-कै०प्रम/2148—संविधान के अनु-च्छेद 243(1) में किए गए उपबंध के अनुसार राजभाषा नीति में हिन्दी संघ की राजभाषा घोषिक की गई है। इस संघ को लागू करने के लिए क्षेत्र सरकार तथा केंद्रीय उपक्रमां, नियमों, निकायों एवं राष्ट्रीय अंकों द्वारा वि के कर्मचारियों का हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण तथा हिन्दी भाषाविधि का महाकांक्षीन प्रशिक्षण दिया जाता है। हिन्दी शिक्षण गणना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण जुलाई, 1952 से प्रारम्भ किए गए थे और तब से देश भर में विभिन्न पूर्णकालिक तथा अर्धकालिक केंद्रों पर इनका आयो-

जन हुआ रहा है। सरकार का यह प्रयास है कि इन प्रशिक्षणों के माध्यम से हिन्दी न केवल बाल कर्मचारियों का हिन्दी का ध्यान और अर्जित कराया जाए ताकि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग प्रयोग हो सके।

2 आठवीं पंचवर्षीय गणना के लिए नियुक्त राजभाषा संबंधी कार्यक्षेत्र में यह अनुमान लगाया था कि वंश में अभी 15-85 लाख एम कर्मचारी हैं। किन्तु हिन्दी का कार्यसाधक मान प्रदान किया जाता है। कार्यक्षेत्र ने यह सिफारिश की थी कि राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिन्दी के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का इस प्रकार से विस्तार किया जाए जिससे ये सभी कर्म-चारी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर सकें। कार्यक्रमों की सिफारिशों के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना में हिन्दी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार तथा उभने यह धारणा है कि कार्यक्रम तैयार किए गए। अर्थात् राजभाषा की कमी के कारण इनमें पूर्ण तरह से लागू कर पाना संभव नहीं हो रहा है।

3 उक्त एक बार हिन्दी प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के विस्तार को ध्यान में रखते तैयार की गई है। इसी वृत्ति और यह भी अनुभव किया जा रहा है कि ये कार्यक्रम स्तुतिबद्ध होते जा रहे हैं और इनमें नियोजितों तथा प्रशिक्षार्थियों की रुचि घटने को साथ ही साथ इनकी उपयोगिता पर भी प्रश्न खिन्न लगने लग रहे हैं। यद्यपि इन कार्यक्रमों का 1974 में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षण किया गया था और उसकी सिफारिशों के अनुसार कुछ परिवर्तन भी किए गए, परन्तु वर्तमान परि-स्थितियों में इन कार्यक्रमों की आवश्यकता तथा उपयोगिता का नए सिरे से निर्धारण आवश्यक है। ताकि उन्हें उनके अनुसूच बनाया जा सके। इस दृष्टि से हिन्दी प्रशिक्षण के इन सभी कार्यक्रमों का नए सिरे से पुनरीक्षण करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न विधित संचित शीठ करण का निर्णय किया है :-

अध्यक्ष

(1) संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

सदस्य

- (2) श्री राम लाल पारीख, कलनायक, गजराज विद्यापीठ
- (3) श्री धारका दास बंद, प्रधान मंत्री, राजभाषा प्रचार समिति, वध।
- (4) निदेशक केंद्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा
- (5) निदेशक, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली

- (6) प्रो./डा. (श्रीमती) वी. सा. आनन्द, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली ।
- (7) प्रा. अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, भारतीय भाषा संस्थान, मेसूर ।
- (8) श्री गिरिषा चन्द्र, समुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), कर्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, एड्स दिल्ली ।

#### सदस्य-संविद्

- (9) निदेशक, केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।

4. उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त समिति अपनी आवश्यकता-नुसार किसी भी एं.स. अन्य सदस्यों को मनोनीत कर सकती है या उसके कार्य निष्पादन में सहत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सके ।

5. समिति अपनी कार्य पद्धति स्वयं निर्धारित करगी ।

6. समिति निम्नलिखित विषयों पर अपना प्रतिबंधन प्रस्तुत करेगी :—

- (1) हिन्दी शिक्षण के विभिन्न कार्यक्रम की अथ तक को उपलब्ध तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति लागू करने में उनका योगदान । उनके वर्तमान दृष्टिकोण (स्ट्रक्चर) तथा व्यवस्था संबंधी (आर्गनाइजेशन) स्वरूप का परीक्षण तथा उनमें सामयिक आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन ।
- (2) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियुक्त कार्यदल को रिपोर्ट के प्रकाश में आवेग प्राप्त शिक्षकों के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या को सही आकलन तथा उसके आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्गठन और विस्तार । संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के खंड-3 में सिफारिश की है कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए अब वर्तमान कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण वर्ष 1990 तक पूरा कर लिया जाए तथा 'ग' क्षेत्र में यह प्रशिक्षण अधिक से अधिक 1993 तक पूरा कर लिया जाए । इस समिति ने यह सिफारिश भी की है कि यह भारी ज्ञाने जाने कर्मचारियों को सेवा के प्रारम्भ में ही हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और यह व्यवस्था पूर्णकालिक हो । वर्तमान अंशकालिक व्यवस्था को पूर्णकालिक व्यवस्था में बदला जाए और प्रशिक्षण में भर्षे गए कर्मचारियों के स्थान पर स्थापना-पद्धति नियुक्ति करने की सुविधा प्रदान की जाए । हिन्दी प्रशिक्षण के अंतर्गत यद्यपि अंशकालिक प्रशिक्षण को साथ ही साथ पूर्णकालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है, तथापि पूर्णकालिक आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के स्थान पर स्थापना-पद्धति नियुक्तियों का प्रावधान नहीं है । संसदीय राजभाषा समिति की उपर्युक्त सिफारिश सहत्वपूर्ण है तथा हिन्दी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनर्गठन और विस्तार के संबंध में सिफारिशों करते समय पुनर्प्रशिक्षण समिति संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखेगी ।
- (3) पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, पठन-पाठन की अन्य सामग्री तथा पठन-पाठन की विधियाँ —प्रशिक्षण

कार्यक्रम को ये सहत्वपूर्ण शैक्षिक पद्धति है और समय-समय पर इनकी समीक्षा करने के मद्देन में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा सिफारिशों की गई है । इसके लिए विभाग को अधिकतर केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य संस्थानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है । समिति इन शैक्षिक पद्धतियों पर गहन रूप से विचार कर अपनी सिफारिशों करे ।

- (4) परीक्षाओं का आयोजन तथा पाठ्यक्रम से उनकी संबंधिता :—विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परीक्षाएं परीक्षा केंद्रों द्वारा ही जाती हैं । प्रतिवर्ष दो बार लगभग 60,000 में भी अधिक कर्मचारियों की परीक्षा आयोजित होती है । यह एक बहुत कार्य है जिसके शैक्षिक तथा व्यवस्था संबंधी बाधाएँ हैं। पहलु सहत्वपूर्ण हैं । वर्तमान परीक्षा केंद्रों इस दृष्टि से काफी कमजोर दिखाई देते हैं जिसके कारण परीक्षाओं के आयोजन में ना-ना प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं । परीक्षाओं को अधिक सभ्यतापूर्ण ढंग से आयोजित करने तथा निर्धारित पाठ्यक्रम से उनकी संबंधिता बनाए रखने का दृष्टि से समिति परीक्षा संबंधी व्यवस्था में सुधार करने की सिफारिश करे ।

- (5) हिन्दी प्रशिक्षण की अनिवार्यता में छूट और उसका वर्तमान स्तर :—कुछ वर्गों के कर्मचारियों को हिन्दी के अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट दी गई है । सामान्य रूप में यह छूट केवल उन कर्मचारियों को दी जाती चाहिए जिन्हें हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त है तथा जो अपना सरकारी भाषा शिक्षा कठिनाई को कर सकते हैं । इस संबंध में विभाग द्वारा दो समय-समय पर निवेदन प्रसारित किए गए, समिति उनकी समीक्षा कर अपनी सिफारिशों करे ।

- (6) प्रशिक्षण की व्यवस्था :—हिन्दी प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं :—
  - (1) पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान और उसके पांच उप-संस्थानों में किया जाता है ।
  - (2) अंशकालिक प्रशिक्षण हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक तथा अंशकालिक केंद्रों में दिए जाते हैं । पूर्णकालिक केंद्रों में यह प्रशिक्षण हिन्दी प्राध्यापकों द्वारा दिया जाता है तथा अंशकालिक केंद्रों में इस कार्य के लिए मातृभाषा के आधार पर प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं ।
  - (3) हिन्दी भाषा तथा हिन्दी टाइपनेशन के पचास पाठ्यक्रम प्रकाशित हुए हैं और संबंधित कर्मचारियों तथा एं.स. कर्मचारियों के लिए आयोजित होते हैं, जिनका पदांकन उन स्थानों पर है, जहाँ हिन्दी शिक्षण योजना का कोई केंद्र उपलब्ध नहीं है । हिन्दी टाइप का पचास पाठ्यक्रम केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित होता है और हिन्दी भाषा का पचास पाठ्यक्रम केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान (राजभाषा विभाग) एवं केंद्रीय हिन्दी निदेशालय (मातृभाषा विभाग विकास संकाय) द्वारा आयोजित किए जाते हैं । केंद्रीय हिन्दी

प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले य दत्त कार्यक्रम वर्ष 1990-91 से प्रारम्भ हुए हैं।

उपयुक्त दोनों पाठ्यक्रमों की वर्तमान स्थिति का गहन रूप से अध्ययन कर समिति इनके संबंध में अपनी सिफारिश करे।

- (7) द्वितीय प्रोत्साहन तथा उनका उपयोगिता :—हिन्दी भाषा तथा हिन्दी टंकण व मासुलिपि के वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर प्रशिक्षार्थियों को द्वितीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इनमें से कुछ द्वितीय प्रोत्साहन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों से भी जुड़ा हुआ है। चूंकि द्वितीय प्रोत्साहन इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण रहे हैं, अतएव इनके संबंध में मसवीय राजभाषा समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन के खंड-3 में भी यह सिफारिश की गई है कि वर्तमान प्रोत्साहन व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाया जाए तथा निर्जी प्रयत्नों से, पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को एकमुष्ट पुरस्कार की राशि दोगुनी कर दी जाए। संसदीय राजभाषा समिति की इस सिफारिश का ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण समिति इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार कर सिफारिश करे।

- (8) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रशिक्षकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संबंधों में जुड़ी समस्याएँ :—हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को संदर्भ अभी तक इस प्रकार से गाँठ नही हुई है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नियुक्त कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान उपयुक्त समय पर पवान्तितियाँ प्राप्त कर सकें। यद्यपि प्रशिक्षण दत्त कार्य कर्मचारियों का प्राध्यापकों तथा सहायक निदेशकों के पदनाम दिए गए हैं परन्तु इनका वर्तमान स्तरीकाल शिक्षकों तथा अनुभाग अधिकारियों के समकक्ष ही है। चूंकि यह समस्या कर्मचारियों के कल्याण तथा उनकी व्यवसायिक प्रगति से जुड़ी है, अतएव समिति इन समस्याओं का अध्ययन कर अपनी सिफारिश करे।

- (9) स्वीच्छक संस्थाओं की भागीदारी :—कर्मचारियों के लिए आयोजित होने वाले हिन्दी शिक्षण कार्यक्रमों में अभी तक स्वीच्छक संस्थाओं की सीधा भागीदारी नहीं है। यद्यपि स्वीच्छक संस्थाएँ ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित करती हैं जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी उनके द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने पर हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जा सकता है। तथापि स्वीच्छक संस्थाओं की भागीदारी को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर विचार कर समिति अपनी सिफारिश करे।

- (10) अन्य विषय :—उक्त विषयों के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित किसी भी सूक्ष्म पर जिम्मेदारिती महसूस करने और आवश्यक संसानी का, अपनी सिफारिशों कर सकती है।

7 समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना प्रतिवेदन तारीख 31-12-1991 तक सरकार को प्रस्तुत करेगी।

### आवेष

आवेष दिया जाता है कि

- (1) इस सरकार की प्रतिनिधि प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दी जाए।
- (2) इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

महेश नाथ  
संयोजक सचिव

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अग 1991

संज्ञाप

सं. जे-13012/12/89-सामान्य-सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग की वैज्ञानिक गलतफहमी समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया है :—

- 1 श्री लक्ष्मण कुमार अध्यक्ष  
अनुपूर्व सचिव (पेट्रोलियम)
- 2 डा० ए० पी० कुव्वाकर सदस्य  
डेन (शोध और विकास)  
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी,  
पोवाई, बम्बई
- 3 प्रो० के० वासुदेव, सदस्य  
रसायन अभियंत्रण विभागाध्यक्ष,  
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,  
नई दिल्ली।
- 4 डा० ए० वर्धराजा, सदस्य  
अनुपूर्व मुख्य परामर्शदाता,  
योजना आयोग,  
नई दिल्ली।
- 5 राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला सदस्य  
द्वारा नामित, पुणे
- 6 डा० टी० एस० आर० प्रसाद राव सदस्य  
निदेशक,  
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान,  
बेहलपूर।

- 7 डा० जे० एन० बरुआ, निदेशक,  
क्षेत्रीय शोध प्रयोगशाला,  
जोरहाट (असम) । सचिव
- 8 डा० ए० जी० रामा राव, निदेशक,  
क्षेत्रीय शोध प्रयोगशाला,  
हैदराबाद । सचिव
- 9 श्री एन० के० शर्मा, निदेशक,  
राष्ट्रीय शोध विकास निगम,  
नई दिल्ली । सदस्य
- 10 श्री एन० विश्वाम,  
उप-सहानिदेशक,  
प्रौद्योगिकी विकास महानिदेशालय,  
उद्योग भवन,  
नई दिल्ली । सदस्य
- 11 श्रीमती ललिता बी० सिंह,  
सलाहकार (पी० सी०),  
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग,  
नई दिल्ली । सदस्य
- 12 इंडियन पेट्रोकेमिकल्स का० लि०  
(आर एंड डी), डायरेक्टोरेट  
द्वारा नामित,  
बड़ौदा । सदस्य
- 13 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान  
परिषद् द्वारा नामित,  
रफी मार्ग, नई दिल्ली । सदस्य
- 14 डा० पी० के० सुखोपाध्याय,  
निदेशक (शोध और विकास)  
इंडियन आयल कारपोरेशन लि०,  
फरीदाबाद । सदस्य
- 15 श्री पी० के० गोयल,  
कार्यकारी निदेशक,  
पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान मंत्र,  
नई दिल्ली । सदस्य
- 16 डा० आर० कृष्णामूर्ति,  
निदेशक (तकनीकी),  
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड,  
नई दिल्ली । सदस्य
- 17 डा० जी० जयारामा राव,  
कार्यकारी निदेशक,  
उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र,  
नई दिल्ली । सदस्य
- 18 सलाहकार (रिफाइनरी),  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग,  
नई दिल्ली सदस्य-सचिव

2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग से सचिव (पेट्रो-नियम) संयुक्त सचिवों और सलाहकार (अन्वेषण) को समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाएगा। अध्यक्ष, समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अथवा समिति को सहायता देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों)को भी आमंत्रित कर सकते हैं।

3 समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:—

“विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी नीतियों पर और उन्हें बढ़ाने और रसायनों के रूप में हाइड्रोकार्बन के कच्चे तेल के अधिन-तम संसाधन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्यान्वित करने के उपायों पर सलाह देना।”

4. समिति का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के लिए होगा। समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार होंगी। परन्तु कम से कम तिमाही से एक बार होंगी और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग से सरकार की समय-समय पर उपयुक्त सिफारिशें करेंगी।

5 समिति के लिए आवश्यक सचिवालय सहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा दी जायेगी।

6. समिति के सदस्यों को निम्न प्रकार का पारिधमिक नहीं दिया जायेगा। तथापि, गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते पर होने वाला खर्च भारत सरकार द्वारा यत्न किया जायेगा। सरकारी अधिकारियों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों पर होने वाला यात्रा भत्ते/महंगाई भत्तों का खर्चा सम्बन्धित विभाग/उपक्रम द्वारा वहन किया जाएगा। समिति पर होने वाला खर्चा तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।

#### आदेश

आदेश दिया जाना है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, राष राज्य क्षेत्र के प्रशासकों, लोक सभा, राज्य सभा सचिवालयों और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाना है कि आम सूचना हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

राजन राज शाह,  
संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय

(सहिष्ठा एवं ज्ञान विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई, 1991

संकल्प

सं० 1-36/90-के० सं० 70-वी०—भारत सरकार श्रीमती थकुल पटेल को अगले आदेश प्रति एक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

की अध्यक्ष नियुक्त करनी है। यह आदेश उस तारीख से लागू होगा जिससे वह उस पक्ष का कार्यभार ग्रहण करेंगी।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाए,—

1. श्रीमती प्रकुम पटेल, के-2, कफ कॉमन, बग परेड, कोलाहा, बम्बई।
2. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
3. सभी राज्य सरकारें/राज्य शासित प्रदेश प्रशासन।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
5. राष्ट्रपति सचिवालय।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय।
8. योजना आयोग।
9. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय।
10. पक्ष सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
11. महानिरीक्षक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
12. कम्पनी कार्य विभाग।
13. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
14. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी बिधि बोर्ड, कानपुर।
15. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
16. राज्य समाज कल्याण महासंघकार बोर्डों के सभी अध्यक्ष।
17. समाज कल्याण मंत्री/मन्त्रि/संयुक्त मन्त्रि के निजी सचिव।
18. राज्य/संघ शासित प्रदेशों के राज्यपालों/प्रशासकों/उप-राज्यपालों/मुख्य आयुक्तों के निजी सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मंजू सेनापति  
उप-सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 1991

सं० क्र०-16013/1/91-ई०एस०ए० (इश्यू० ई०)—  
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(i) के अनुसरण में, भारत सरकार/राज्यद्वारा श्रम राज्य मंत्री के स्थान पर भारत सरकार के श्रम उपमंत्री को तत्काल प्रभाव से अगला आदेश जारी किए जाने तक उक्त केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कामकाज करनी है।

2. तदनुसार भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित समय-समय पर यथागोष्ठित श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० क्र०-16012/2/89-ई० एस० ए० (इश्यू० ई०), दिनांक 25 जून, 1990 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं,—

कम संख्या 1 के सामने वर्तमान प्रविष्टि के लिए, अर्थात्—

“श्रम राज्य मंत्री,

भारत सरकार,

नई दिल्ली।”

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :

“श्रम उप मंत्री,

भारत सरकार,

नई दिल्ली।”

दिनांक 12 जुलाई 1991

सं० क्र०-16012/1/88-ई० एस० ए० (रा० श्र० सं०)—  
जबकि दिनांक 17 दिसम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या क्र०-16012/1/88-ई० एस० ए० (रा० श्र० सं०) के तहत श्रम एवं कल्याण राज्य मंत्री को राष्ट्रीय श्रम सम्मान का अध्यक्ष अधिस्थित किया गया था।

अब उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया जाए :  
विद्यमान प्रविष्टि

“श्रम एवं कल्याण राज्य मंत्री—अध्यक्ष”

के स्थान पर

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी—

“श्रम राज्य मंत्री—अध्यक्ष”

ए० के० चन्दा,  
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd July 1991

CORRIGENDA

No 78-Pres/91—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 65-Pres/74, dated 26th April, 1974, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated 11th May, 1974 relating to 'Mention-in-Despatches' :—

Sl. No 11

For : Lt Col Shalendra Raj Bahuguna (IC-7205), 15 Kumaon.

Read : Lt Col Shalendra Raj Bahuguna (IC-7305), 15 Kumaon

No. 79-Pres/91—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 54-Pres/90, dated 26th January, 1990, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated Saturday, the 28th July, 1990 relating to 'Mention-in-Despatches' :—

For : Operations in Slachen

Read : Operations in Slachen and Line of Control in J&K

A. K. UPADHYAY, Director

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi-110003, the 26th July 1991

## RESOLUTION

No. 19011/25/91-CHTI/2148.—In accordance with the provisions contained in Article 343(1) of the Constitution, Hindi in Devnagari script has been declared as the Official Language of the Union. With a view to ensuring the implementation of this provision, employees of Central Government, Central Undertakings, Corporation, Bodies and Nationalised Banks etc are imparted in-service training of Hindi language, Hindi Typewriting and Hindi Stenography. These training courses were started in July, 1952 under the aegis of Hindi Teaching Scheme and since then they are being organised all over the country at various full time and part time Centres. It is the endeavour of the Government that through such training programmes, adequate knowledge of Hindi is provided to the non-Hindi knowing employees so that Hindi is progressively used in the official work.

2. The Working Group on Official Language set up for the Eighth Five Year Plan had estimated that, at the beginning of the Eighth Plan there were about 15.85 lakh employees yet to be imparted working knowledge of Hindi. The Working Group had recommended that the Hindi Training programmes of the Department of Official Language should be so expanded that all such employees acquire working knowledge of Hindi by the end of Eighth Five Year Plan. In accordance with the recommendation of the Working Group, programmes were chalked out to expand the Hindi training programmes and to make them multi-dimensional during the course of Eighth Five Year Plan. However, it has not been possible so far to implement them fully for want of adequate resources.

3. While on one hand, schemes have been prepared to expand various Hindi training programmes, on the other, it is increasingly being felt that these programmes are getting more and more conventional and both employees as well as employers are losing interest in them and have even started raising question marks on their utility. Even though these programmes were reviewed in 1974 by a high-level Committee and some changes were also made in accordance with their recommendations, yet in the present context it has become necessary to redefine the need and usefulness of these programmes so that they are redesigned and brought in tune with them. From this point of view the Government of India have decided to get the entire parent of Hindi Training Programmes reviewed and for which the following Committee has been constituted:—

## CHAIRMAN

- (1) Joint Secretary,  
Department of Official Language.

## MEMBERS

- (2) Shri Ram Lal Parock,  
Vice Chancellor,  
Gujarat Vidhyapeeth.
- (3) Shri Dwarka Das Veda,  
Pradhan Mantri,  
Rashtra Bhasha Prachar Samiti,  
Wardha.
- (4) Director,  
Central Hindi Institute,  
Agra.
- (5) Director,  
Central Hindi Directorate,  
New Delhi.
- (6) Prof. (Dr) Smt. V. S. Anand,  
National Council for Educational Research and  
Training, New Delhi.
- (7) Prof. Akhilosh Kumar Srivastava,  
Institute of Indian Languages,  
Mysore.

- (8) Shri Girish Chandra,  
Joint Director (Training),  
Department of Personnel & Training,  
New Delhi.

## MEMBER-SECRETARY

- (9) Director,  
Central Hindi Training Institute,  
New Delhi.

4. The Committee may co-opt any other person as its member who may in its opinion be able to make some significant contribution to its work.

5. The Committee will, itself determine its procedure of work.

6. The Committee shall submit its report on the following subjects:—

- (1) Achievements so far, of various Hindi teaching schemes and their contribution in the implementation of the Official Language Policy as laid down by the Government of India. Scrutiny and examination of the existing structural and organisational aspects of these programmes and changes, if any, required to meet the present needs.
- (2) A realistic assessment of the number of yet to be trained employees for various training courses in the light of the report of the Working Group set up for the Eighth Five Year Plan and re-organisation and expansion of training schemes on the basis of that. The Committee of Parliament on Official Language has recommended in Part III of its report that the Hindi training for the remaining staff should be completed by the year 1990 in 'A' and 'B' regions and in 'C' region, this training should be completed latest by 1993. This Committee has also recommended that arrangements should be made for Hindi training of newly recruited staff on a full time basis at the beginning of their service itself. The present part time system should be changed to full-time and facilities may be provided for posting of a substitute in place of the employees sent for training. Even though, facilities are available for full-time training alongwith part-time training under the Hindi Teaching Scheme, yet, there is no provision for posting of substitute in place of persons deputed for training in full-time courses. These recommendations of the Committee of Parliament on Official Language are important and while making recommendations for re-organisation and expansion of the Hindi training programmes, the Review Committee shall take them into consideration.
- (3) Syllabus, Text-Books other materials for teaching and learning and teaching/learning methods:— These are the important academic aspects of training programmes and the Committee of Parliament on Official Language has recommended for their review from time-to-time. For this purpose, the Department has to depend mostly upon the Central Hindi Training Institute and other such organisations. The Committee while making its recommendations may seriously consider these academic aspects.
- (4) Organisation of the Examinations and their linkages with the syllabus:—The examinations of the training courses organised by the Department, are being conducted by the Examination Wing. The examinations are conducted twice a year for more than 60,000 employees. This is a gigantic task of which both academic and organisational aspects are equally important. From this point of view the present Examination Wing is an extremely weak unit, as a result of which different kinds of problems arise in conducting the examinations. The Committee may look into these problems and may recommend necessary reforms in the examination system so that the examination are conducted more efficiently maintaining closer linkages with the prescribed syllabi.



- (5) Exemption from compulsory Hindi training and its present conditions :—Employees of various categories have been exempted from compulsory Hindi training. In a normal course this exemption should be granted to only to such of the employees as have acquired the expected working knowledge of Hindi and can do their official work in Hindi without difficulty. The Committee may review the instructions issued by the Department in this regard from time-to-time and make its recommendations.
- (6) Arrangements for training :—Three types of arrangements are available at present for Hindi training—(i) Full-time intensive training is being provided by the Central Hindi Training Institute and its 5 Sub-Institutes. (ii) Part-time training is imparted through full-time and part-time centres under the Hindi Teaching Scheme. In full-time centres, this training is given by Hindi Pradhyapak and in the part-time centres part-time instructors are appointed for this work on honorarium basis. (iii) Correspondence Courses for Hindi language and Hindi Typewriting are being conducted for employees on operational duty and for those who are posted at places where Centres of Hindi Teaching Scheme do not exist. Hindi Typewriting Correspondence Course is being organised by Central Hindi Training Institute and the Correspondence Courses for Hindi language are being organised by the Central Hindi Training Institute (Department of Official Language) and Central Hindi Directorate (Ministry of Human Resources Development). Both of the courses being organised by the Central Hindi Training Institute have been started from the year 1990-91.
- The Committee may make recommendations in respect of all the three above-mentioned courses after making an in-depth study about their present status.
- (7) Financial incentives and their utility :—Financial incentives are being provided to the trainees on their successful completion of the training programmes of Hindi language, Hindi Typewriting and Hindi Stenography. Out of these, some incentives are linked with the marks obtained in the examinations. Since the financial incentives are the major attractions of these training programmes, the Committee of Parliament on Official Language in the Third part of its Report has recommended that the present scheme of incentives may be made more attractive and the amount of lump-sum awards should be doubled for those employees who receive their training through their own efforts or through the Correspondence Courses. The Review Committee may make its recommendations after considering the various aspects of incentives scheme as also after taking into account the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language.
- (8) Problems related to the Cadres of Instructors, Officers and Staff for conducting training programmes :—The Cadres of staff appointed under the Hindi Teaching Scheme have not been reorganised so as to make it sure that the employees recruited for training programmes are able to get their promotions at appropriate times during their service careers. Even though, the employees recruited for imparting training have been designated as Pradhyapak and Assistant Directors but their pay scales are equivalent to those of Post Graduate teachers and Section Officers only. Since this problem is linked with the welfare of staff and their career advancement, the Committee may look into it and make appropriate recommendations.
- (9) Participation of Voluntary Organisations :—The Voluntary Organisations have, so far, not been directly involved in the Hindi training programmes being organised for the employees. Even though, Voluntary Institutions organise many such programmes in which the staff trained by them after passing the prescribed examinations,

acquire sufficient knowledge of Hindi and they can be deemed to have acquired the working knowledge, yet, it is important to explore the ways and means to increase the participation of the Voluntary Organisations in the Hindi training programmes and the Committee may consider this issue and make its recommendations.

- (10) Other Items :—Apart from the above items, the Committee may make its recommendations on any other issue relating to training programmes which it may consider important and necessary.
7. It is expected from the Committee that it would submit its report to the Government by 31-12-1991.

#### ORDER

It is ordered that :—

- (1) Copies of this Resolution be forwarded to the Chairman of the proposed Committee and each of its members.
- (2) It should be published in the Gazette of India.

MAHENDRA NATH  
Jt. Secy.

---

#### MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (DEPARTMENT OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

New Delhi, the 11th June 1991

#### RESOLUTION

No. J-13012/12/89-Gen.—It has been decided by the Government to reconstitute the Scientific Advisory Committee for the Department of Petroleum & Natural Gas as under :—

#### Chairman

1. Shri Lovraj Kumar,  
Ex-Secretary (Petroleum)

#### Members

2. Dr. A. P. Kudchadker,  
Dean (R&D), Indian Institute of Technology,  
Powai,  
Bombay.
3. Prof. K. Vasudeva,  
Head of Chemicals Engineering Deptt.,  
Indian Institute of Technology,  
New Delhi.
4. Dr. S. Varadaraja,  
Ex-Chief Consultant,  
Planning Commission,  
New Delhi.
5. Nominee of National Chemical Laboratory,  
Pune.
6. Dr. T. S. R. Prasada Rao,  
Director, Indian Institute of Petroleum,  
Dehradun.
7. Dr. J. N. Barua, Director,  
Regional Research Laboratory,  
Jorhat (Assam).
8. Dr. A. V. Rama Rao,  
Director,  
Regional Research Laboratory,  
Hyderabad.
9. Shri N. K. Sharma,  
Director,  
National Research Development Corporation,  
New Delhi.

*Members*

10. Shri N. Biswas,  
Dy. Director General,  
Directorate General of Technical Development,  
Udyog Bhavan,  
New Delhi.
11. Smt. Lalitha B. Singh,  
Advisor (PC),  
Deptt. of Chemicals & Petrochemicals,  
New Delhi.
12. Nominee of  
Indian Petrochemicals Corpn. Ltd.,  
(R&D) Directorate,  
Baroda.
13. Nominee of  
Council of Scientific & Industrial Research,  
Rafi Marg,  
New Delhi.
14. Dr. P. K. Mukhopadhyay,  
Director (R&D),  
Indian Oil Corporation Ltd.,  
Faridabad.
15. Shri P. K. Goel,  
Executive-Director,  
Petroleum Conservation, Research Association,  
New Delhi.
16. Dr. R. Krishnamurthy,  
Director (Technical),  
Engineers India Ltd.,  
New Delhi.
17. Dr. G. Jayarama Rao,  
Executive Director,  
High Technology Centre,  
New Delhi.

*Member-Secretary*

18. Advisor (Refinery),  
Deptt. of Petroleum & Natural Gas,  
New Delhi

2. Secretary, Petroleum, Joint Secretaries and Advisor (Exploration) in the Department of Petroleum and Natural Gas will be permanent invitees to the Committee Meetings. The Chairman may also invite any other person(s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee.

3. The terms of reference of the Committee will be as under:—

"To advise on policies relating to Science and Technology and measures to implement them to ensure optimum processing of hydrocarbon raw material for use as fuels and chemicals".

4. The term of the Committee will be for a period of 2 years from the date of issue of this Resolution. The Committee shall meet as often as necessary but at least once a quarter and will make suitable recommendations to the Department of Petroleum and Natural Gas from time to time.

5. The Secretarial assistance required to the Committee will be provided by the Department of Petroleum and Natural Gas.

6. No remuneration will be paid to the members of the Committee. However, the expenditure on TA/DA of the non-official members will be met by the Government of India. The TA/DA of Government officials/representative of Central Public Sector Undertakings will be met by the concerned Departments/Undertakings. The expenditure on the Committee will be borne by the Oil Industry Development Board.

**ORDER**

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administration, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. R. SHAH, Jt. Secy.

**MINISTRY OF WELFARE**

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 16th May 1991

**RESOLUTION**

No. 1-36/90-CSWB.—The Government of India is pleased to appoint Smt. Bakul Patel as Chairman of the Central Social Welfare Board till further orders.

This order will take effect from the date she assumes charge.

**ORDER**

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :

1. Smt. Bakul Patel, K-2, Cuffe Castle, Cuffe Parade, Colaba, Bombay
2. All the Members of the CSWB
3. All the State Governments/UTs
4. All the Ministries/Deptts. of the Govt. of India
5. President's Secretariat
6. Cabinet Secretariat
7. Prime Minister's Office
8. Planning Commission
9. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat
10. PTB
11. AGCR, New Delhi
12. Department of Company Affairs
13. Registrar of Companies, New Delhi
14. Regional Director, Company Law Board, Kanpur
15. Executive Director, CSWB, New Delhi
16. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards
17. PSs to Minister of State for Women & Child Development/Secretary/JS(P)
18. PSs to Governors/Administrators/Lt. Governors/Chief Commissioners of all State/UT Admu.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MANJU SENAPATY, Dy. Secy.

## MINISTRY OF LABOUR

The 12th July 1991

New Delhi, the 10th July 1991

No. Q-16015/1/91-ESA(WE)(.)—In pursuance of Rule 3(i) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby nominate Deputy Minister for Labour, Government of India instead of Minister of State for Labour, as the Chairman of the said Central Board for Workers Education with immediate effect and until further orders.

2 The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/2/89-ESA(WE) dated the 25th June, 1990 published in the Gazette of India, Part-I, Section 1 as amended from time to time :—

For the existing entry against serial No. 1 viz :—

"Minister of State for Labour,  
Government of India, New Delhi."

The following shall be *substituted* viz :—

"Deputy Minister for Labour,  
Government of India, New Delhi."

No. Q-16012/1/88-ESA(NLI).—WHEREAS, Minister of State for Labour & Welfare was notified as President of National Labour Institute *vide* Notification No. Q-16012/1/88-ESA(NLI), dated the 17th December, 1990.

NOW in the said Notification, the following changes may be made :—

For the existing entry :—

"Minister of State for Labour — President"  
and Welfare

The following entry shall be *substituted* :—

"Minister of State for Labour — President"

A. K. CHANDA, Director

